मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने, कृषि लागत कम करने और उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़ एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

- **मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की**
- **मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसैसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।**

रांची, 17 अगस्त। जेपीएससी - जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन में सोमवार देर रात बड़ा मोड़ आया। लंबे समय तक चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख मांगें मानने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर करीब तीन घंटे तक गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। साथ ही, टीडीपीएल के माध्यम से हुई भर्तियों को भी रद्द करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 से अब तक टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द होंगी।

मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद आंदोलनरत छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, "हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?"

जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

- **नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।**

नई दिल्ली, 17 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा, क्षेत्रीय विविधता और सामाजिक समावेश का व्यापक संतुलन देखने को मिला है। सोमवार को जारी नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में देश के 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। करीब 65 सदस्यों की नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन निबीन ने सोमवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वरिष्ठ नेता राम माधव समेत, 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हरीश द्विवेदी समेत, आठ नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

भाजपा की विज्ञिप्त के मुताबिक, वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लब देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व कविता पाटीदार, के सुरेन्द्रन, भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, संदीप पाठक, फांग्नोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, एम वेंकटेशन , मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, जय प्रकाश को सौंपा गया है। वहीं, तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और महेन्द्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। डॉ. संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा को बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ के सह संयोजक ऋतुराज और विष्णु वर्धन रेड्डी को बनाया गया है।

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा, मन्नालाल रावत को अनुसूचित जनजाति और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अनिल बलूनी को फिर मीडिया संयोजक बनाया गया है। आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक बनाया गया है। दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को सह संयोजक बनाया गया है।

नितिन नबीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

- **सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कार्यवाही कर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम किये**
- **केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी।**

नई दिल्ली, 17 अगस्त। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली के जरिए समन्वित बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया। इसमें 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी समूह 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ़्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

शहजाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूनावाला ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। इनमें तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में उनका मजबूत प्रदर्शन, नागपुर से उनका संबंध और आरएसएस से उनके करीबी रिश्ते प्रमुख हैं। इसके अलावा, विपक्षी नेताओं की ओर भी से बार-बार यह दावा किया जाता रहा है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तथा शिक्षा जैसे किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की समय -समय पर होने वाली चर्चाओं और केन्द्र में अनुभवी प्रशासकों की भाजपा की जरूरत ने भी इन अटकलों को लगातार हवा दी है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फडणवीस की मुलाकात ने उनके राष्ट्रीय स्तर पर संभावित भविष्य को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं को फिर से जीवित कर दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में भाजपा और आरएसएस के हलकों में उन्हें कभी-कभार भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखा गया है। इसके पीछे उनका प्रशासनिक अनुभव, अपेक्षाकृत कम उम्र और संघ परिवार में उनकी मजबूत जड़ें बताई जाती हैं।

कुछ राजनीतिक विश्लेषणों में यह भी कहा गया है कि उन्हें मोदी के बाद दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, फडणवीस खुद पहले भी मोदी के उत्तराधिकारी संबंधी अटकलों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि मोदी ही पार्टी के नेता हैं और 2029 में भी वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

आरएसएस के दबाव में निकट भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन के दावे फिलहाल वास्तविकता पर आधारित होने के बजाय, विपक्ष की ओर से पैदा की गई राजनीतिक अटकलें अधिक दिखाई देते हैं।

अगर फडणवीस अंततः दिल्ली चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। राज्य में भाजपा के सबसे प्रमुख चेहरे और महायुति गठबंधन की हालिया सफलताओं के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक होने के कारण, उनके जाने से मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुले या अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है।

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के साथ गठबंधन के समीकरणों पर भी नए सिरे से बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। इससे जहाँ एक तरफ, सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता की परीक्षा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र भाजपा के भीतर गुटीय खींचतान से जुड़े पुराने विवाद भी फिर उभर सकते हैं।

कतर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से धन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए सत्र के सफल संचालन में सहयोग करेंगे।

"दिमागी नक्सल" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर खुद को संगठित किया है।

स्पष्ट रूप से, मोदी का यह संदेश वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज की आवाजों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है, जिन्हें भाजपा लंबे समय से "अर्बन नक्सल" कहती रही है।

इसमें असहमति, विशेषकर शासन, शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं या हिंदुत्व की प्राथमिकताओं की आलोचना, को वैध राजनीतिक विरोध के बजाय माओवादी विद्रोह के वैचारिक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस टिप्पणी को हताशा का पक्का संकेत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अक्सर अपने आलोचकों को बदनाम करती है और बाद में उन्हीं की मांगों को अपना लेती है। उन्होंने इसके उदाहरण के रूप में जातीय जनगणना का हवाला दिया।

विपक्ष के अन्य नेताओं, जिनमें भाकपा के डी. राजा भी शामिल हैं, ने इस शब्द को असहमति को कलंकित करने और सरकार पर सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बताया है।

'अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

वंदे मातरम् का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यालय इंदिरा भवन में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया।

पहले दो अंतरे गाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा कि गीत गाया जा चुका है और इतना पर्याप्त है। सोनिया गांधी ने इसके बाद राहुल गांधी से कहा कि खड़गे जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनो।

राहुल गांधी ने उन्हें समझाया कि कांग्रेस के कुछ लोगों को पूरा वंदे मातरम् गाने पर आपत्ति है और ध्वजारोहण से पहले इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी।

इसके बाद तय किया गया कि चूंकि अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है, इसलिए पूरा गीत गाया जाएगा।

और इंदिरा भवन में ठीक यही हुआ।

इससे पहले सोनिया गांधी को इशारे करते हुए देखा गया कि वे कुछ कैमरा संचालकों से वहां से हटने और कार्यक्रम की कार्यवाही में बाधा न डालने के लिए कह रही थीं।

मामला यहीं समाप्त हो गया।

लेकिन अमित शाह ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक विवाद बना दिया है। वे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर वंदे मातरम् को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए माफी मांगने की बात कर रहे हैं।

वे केवल माफी ही नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूरे घटनाक्रम की जांच करने और यह रिपोर्ट देने को भी कहा है कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है। एक बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत को नफरत और दुश्मनी की राजनीति में घसीटकर भाजपा द्वारा हिंदू बनाम मुस्लिम विभाजन की आग को जलाए रखने और उससे अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

वंदे मातरम् की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई थी और अब भाजपा इस आग को जलाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, ताकि इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में, सरकार ने आरोप लगाया था कि उत्पाद का प्रचार वास्तव में विमल तंबाकू उत्पादों के लिए सरोगेट विज्ञापन है। इस कानूनी विवाद ने एक बुनियादी समस्या को उजागर किया: केवल तंबाकू और गैर-तंबाकू उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड नाम का होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि विज्ञापन गैर-कानूनी है। रेगुलेटर को दोनों के बीच यह संबंध साबित करना होगा और दिखाना होगा कि देखने में वैध उत्पाद का विज्ञापन असल में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार कर रहा है।

सबूत जुटाने की इस चुनौती की वजह से यह प्रथा अब भी ऐसे धुंधले क्षेत्र (ग्रे एरिया) में बनी हुई है, जहाँ कानून की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

तथापि, विज्ञापन की रणनीति अब और भी बेहतर होती जा रही है। कोई तंबाकू ब्रांड किसी कानूनी ब्रांड विस्तार (ब्रांड एक्सटेंशन) के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रख सकता है, जबकि विज्ञापन में उसी नाम, लोगो, रंग, सेलिब्रिटी, स्लोगन और विजुअल पहचान का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रतिबंधित उत्पाद से जुड़े होते हैं। ग्राहकों को ब्रांड पहचानने के लिए तंबाकू उत्पाद देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

इसीलिए रेगुलेटरी टेस्ट को मुख्य रूप से इरादा साबित करने पर आधारित होने के बजाय ठोस और स्पष्ट पैमानों पर आधारित होना चाहिए।

रेगुलेटर यह जांच सकते हैं कि क्या इसी ब्रांड का इस्तेमाल तंबाकू उत्पादों के लिए भी किया जाता है; क्या कथित रूप से वैध उत्पाद का अपना पर्याप्त और स्वतंत्र रूप से चलने वाला कारोबार है; क्या उसका वितरण और बिक्री वास्तव में होती है; क्या विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध लागू होने से पहले वह वास्तव में एक असली उत्पाद के तौर पर मौजूद था; और क्या उसका विज्ञापन तंबाकू ब्रांड की खास पहचान को बहुत करीब से दोहराता है।

जहाँ इनमें से कई संकेत एक साथ दिखाई दें, वहाँ विज्ञापन देने वाले पर यह साबित करने की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि ब्रांड विस्तार वास्तव में एक वास्तविक और स्वतंत्र कारोबार है।

सेलिब्रिटी के विज्ञापन में शामिल होने की भी विशेष रूप से जाँच होनी चाहिए। कोई एक्टर यह तर्क दे सकता है कि उसने इलायची का विज्ञापन किया, तंबाकू का नहीं। लेकिन अगर विज्ञापन का मुख्य मकसद प्रतिबंधित तंबाकू ब्रांड की पहचान को लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, तो इस अंतर को सही ठहराना लगातार मुश्किल हो जाता है।

उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वैध कारोबारों को कानूनी उत्पादों का विज्ञापन करने से रोका जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी कानूनी उत्पाद को गैर-कानूनी उत्पाद के विज्ञापन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनने से रोका जाए।

इसलिए भारत को ब्रांड विस्तार के लिए एक अधिक स्पष्ट और तकनीक से स्वतंत्र नियम की ज़रूरत है, जिसमें पारदर्शी मानदंड और कड़े दंड का प्रावधान हो। विज्ञापन एजेंसियों और सेलिब्रिटीज़ से भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं की ब्रांड पहचान वाले उत्पादों का विज्ञापन करने से पहले पूरी जाँच-पड़ताल करें।

इस तरह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस सिर्फ़ एक और सेलिब्रिटी विवाद बनकर न रह जाएं। वे एक ऐसे सवाल को सुलझाने का मौका दे सकते हैं जो बरसों से बना हुआ है: कोई उत्पाद कानूनी हो सकता है, लेकिन क्या उसका विज्ञापन कानूनी तौर पर किसी ऐसी चीज़ के विज्ञापन के रूप में काम कर सकता है, जो खुद कानूनी नहीं है?

जब तक इस सवाल का जवाब एक स्पष्ट रेगुलेटरी टेस्ट के ज़रिए नहीं दिया जाता, तब तक सरोगेट विज्ञापन की यह कानूनी खामी प्रतिबंधित ब्रांडों को बाज़ार में अपनी पहचान बनाए रखने का मौका देती रहेगी और उन्हें अपने उत्पाद का खुलकर विज्ञापन करने की ज़रुरत भी पड़ेगी।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-22820427
आवेदन के लिए क्यूआर स्कैन करें

नियमित/संविदा आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की भर्ती

नियमित/संविदा आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/11 (संविदा पद)

पद का नाम	रिक्ति	आयु (31.07.2026 तक) न्यूनतम	आयु (31.07.2026 तक) अधिकतम
उप उपाध्यक्ष (डीवीपी) – साइबर इनोवेशन और सिमुलेशन लैब	1	35	45
उप उपाध्यक्ष (डीवीपी) – सिटिज़न सेंट्रिक इनिशिएटिव्स	1		
उप उपाध्यक्ष (डीवीपी) – सायबर सुरक्षा	2		

(नियमित पद)

पद का नाम	रिक्ति	श्रेणी	आयु (31.07.2026 तक) न्यूनतम	आयु (31.07.2026 तक) अधिकतम
उप प्रबंधक – एआई विशेषज्ञ	25	एमएमजीएस –II	25	35
उप प्रबंधक – साइबर सुरक्षा विश्लेषक	3			
उप प्रबंधक – आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ	2			

विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/12 (नियमित पद)

पद का नाम	रिक्ति	श्रेणी	आयु (31.07.2026 तक) न्यूनतम	आयु (31.07.2026 तक) अधिकतम
प्रबंधक (मैनपावर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट)	1	एमएमजीएस –III	28	40
प्रबंधक (लर्निंग और डेवलपमेंट)	1	एमएमजीएस –III	28	40

विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/13 (संविदा पद)

पद का नाम	रिक्ति	आयु न्यूनतम	आयु अधिकतम
उप–अध्यक्ष (एंटरप्राइज़ और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट)	1	40	48
उप–मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी (एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर)	1	42	50

पात्रता मानदंड (आयु, अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, आवश्यक शुल्क एवं अन्य विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट **https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings** पर लॉग ऑन करें, जहाँ उपरोक्त विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध हैं. इसके साथ आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु एक लिंक भी दी गई है. आवेदन करने और शुल्क भेजने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने एवं अन्य विवरणों के लिए विस्तृत विज्ञापन पढ़ें. कोई अन्य पूछताछ करने के लिए कृपया **"CONTACT US"→"Post Your Query"** लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो कि बैंक की वेबसाइट **(https://sbi.bank.in/web/careers/ post-your-query)** पर उपलब्ध है.

- **आवेदन ऑनलाइन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की तिथि : 07.08.2026 से 27.08.2026 तक.**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 07.08.2026 **महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएम)**

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908